



Daily करेंट अफेयर्स

» 28 जुलाई 2025

NATIONAL AFFAIRS

1. भारत की बंदरगाह दक्षता और वैश्विक निवेश को बढ़ावा देने के लिए MoPSW ने नई दिल्ली में समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया।



जुलाई 2025 में, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने नई दिल्ली, भारत में समुद्री वित्तपोषण शिखर सम्मेलन 2025 का सफलतापूर्वक आयोजन किया। इस सम्मेलन में वरिष्ठ नीति निर्माताओं, वैश्विक निवेशकों, क्षेत्र विशेषज्ञों और उद्योग जगत के नेताओं ने भारत के समुद्री बुनियादी ढाँचे और वैश्विक बंदरगाह प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करने के उद्देश्य से वित्तीय समाधान तलाशने हेतु एक मंच पर भाग लिया।

- यह शिखर सम्मेलन समुद्री अमृत काल विजन (MAKV 2047) के अनुरूप है, जो 2047 तक भारत को एक अग्रणी वैश्विक समुद्री केंद्र के रूप में देखता है। यह विजन देश भर में जहाज निर्माण, बंदरगाह बुनियादी ढाँचे और वित्तीय लचीलेपन को मज़बूत करने पर केंद्रित है।

- केंद्रीय जल संसाधन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने मुख्य भाषण दिया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि भारत के बंदरगाहों ने अपने परिचालन प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार किया है, जिससे जहाजों का औसत टर्नअराउंड समय 4 दिनों से घटकर 1 दिन

से भी कम हो गया है, जिससे वैश्विक बंदरगाह दक्षता में एक मानक स्थापित हुआ है।

- भारत के प्रमुख बंदरगाहों की कंटेनर हैंडलिंग क्षमता में 70% की वृद्धि हुई है, साथ ही कार्गो की मात्रा में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। ये सुधार लक्षित बुनियादी ढाँचे में निवेश और बंदरगाह आधुनिकीकरण के कारण संभव हुए हैं।

Key Points:-

(i) भारत सरकार (GoI) ने स्वचालित मार्ग (AR) के तहत शिपिंग क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति दी है, जिससे तेजी से अनुमोदन संभव होगा और भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री निवेशकों के लिए अधिक आकर्षक बन जाएगा।

(ii) इस क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने समुद्री विकास निधि (MDF) शुरू करने की घोषणा की है - जो बंदरगाहों, शिपयार्ड और संबंधित बुनियादी ढाँचे में नियामक बाधाओं के बिना दीर्घकालिक पूंजी निवेश का समर्थन करने के लिए एक समर्पित वित्तपोषण साधन है।

(iii) इसके अतिरिक्त, मैरीटाइम डिजिटल मैच्योरिटी मैट्रिक्स (FDMM) की शुरुआत से भारत के प्रमुख बंदरगाहों की डिजिटल क्षमताओं का आकलन और संवर्धन करने में मदद मिलेगी। इस उपकरण का उद्देश्य विकसित हो रहे वैश्विक समुद्री व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र का समर्थन करने के लिए स्मार्ट बुनियादी ढाँचा और वास्तविक समय परिचालन पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

2. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुलभता, डिजिटल समावेशन और नेट जीरो लक्ष्यों पर नई पहल के साथ अपने कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे किए।



25 जुलाई, 2025 को, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में 3 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन और नई दिल्ली स्थित संबद्ध परिसरों में सुगम्यता, डिजिटल पहुंच, स्थिरता और नागरिक सहभागिता पर केंद्रित कई पहलों का शुभारंभ किया।

- राष्ट्रपति मुर्मू, जिन्होंने 25 जुलाई 2022 को भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और इस पद पर आसीन होने वाली दूसरी महिला के रूप में पदभार ग्रहण किया, ने समावेशी शासन पर प्रकाश डालते हुए इस अवसर को स्मरण किया। उनके कार्यकाल में सर्वोच्च संवैधानिक पद से जनभागीदारी और पर्यावरणीय नेतृत्व पर ज़ोर दिया गया है।

- सुगम्यता पहल के तहत, राष्ट्रपति भवन, अमृत उद्यान और राष्ट्रपति भवन संग्रहालय को पूरी तरह से दिव्यांगजन-अनुकूल बनाया गया है। इसमें स्पर्शनीय पथ, ब्रेल बोर्ड, रैंप और अन्य सुविधाएँ शामिल हैं जिनका उद्देश्य दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के अनुरूप समावेशी सार्वजनिक पहुँच सुनिश्चित करना है।

- राष्ट्रपति भवन की वेबसाइट और भारत के राष्ट्रपति पोर्टल अब 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिससे राज्यों के नागरिकों के लिए बहुभाषी डिजिटल पहुंच संभव होगी और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परिकल्पित डिजिटल समावेशन को बढ़ावा मिलेगा।

Key Points:-

(i) राष्ट्रपति को मिले 250 से ज़्यादा उपहारों की 'ई-उपहार सीज़न 2' के तहत ऑनलाइन नीलामी की गई है, जिससे प्राप्त आय बाल कल्याण कार्यक्रमों में मदद करेगी। यह डिजिटल नीलामी पहल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और नागरिक समाज को राष्ट्रपति के धर्मार्थ कार्यों से जोड़ती है।

(ii) पिछले वर्ष राष्ट्रपति के भाषणों, कार्यक्रमों और कार्यक्रमों को संकलित करते हुए एक आधिकारिक इलेक्ट्रॉनिक (ई)-पुस्तक का विमोचन किया गया। इसका उद्देश्य जन जागरूकता बढ़ाना और एक ही डिजिटल दस्तावेज़ के माध्यम से राष्ट्रपति पद के कामकाज तक खुली पहुँच प्रदान करना है।

(iii) पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को बढ़ावा देने के लिए, '2027 तक नेट ज़ीरो' पहल शुरू की गई। इसमें भारत की जलवायु प्रतिबद्धताओं के अनुरूप, सौर ऊर्जा संयंत्रों, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित ऊर्जा के उपयोग के माध्यम से राष्ट्रपति भवन को कार्बन-तटस्थ बनाने के कदम शामिल हैं।

3. प्रधानमंत्री मोदी क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए 26 जुलाई 2025 को तूतीकोरिन हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे।



26 जुलाई 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन (थूथुकुडी) हवाई अड्डे पर

अत्याधुनिक नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। यह विस्तार दक्षिणी तमिलनाडु में हवाई, सड़क, बंदरगाह और रेल संपर्क को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ₹4,800-₹4,900 करोड़ की व्यापक बुनियादी ढाँचा परियोजना का हिस्सा है।

- लगभग ₹450 करोड़ की लागत से निर्मित और 17,340 वर्ग मीटर में फैले इस नए टर्मिनल में 21 चेक-इन काउंटर, 3 एयरब्रिज, 7 बैगेज स्कैनर, 4 प्रवेश द्वार और प्रस्थान क्षेत्र में 644 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था है। यह व्यस्त समय में 1,350 यात्रियों और सालाना 20 लाख यात्रियों को संभाल सकता है, जिसे बढ़ाकर 25 लाख यात्रियों तक किया जा सकता है।

- रनवे को 1,350 मीटर से बढ़ाकर 3,115 मीटर कर दिया गया है और 30 मीटर से 45 मीटर चौड़ा किया गया है, जिससे एयरबस A320/A321 जैसे बड़े चौड़े आकार के विमानों को उड़ाना संभव हो गया है। अब रात्रिकालीन लैंडिंग की सुविधा पूरी तरह से उपलब्ध है, जिससे चौबीसों घंटे परिचालन लचीलापन बढ़ा है।

- GRIHA-4 सस्टेनेबिलिटी रेटिंग प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किए गए इस टर्मिनल में 100% LED लाइटिंग, ऊर्जा-कुशल विद्युत और यांत्रिक प्रणालियाँ, और उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए एक ऑन-साइट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है। ये सभी विशेषताएँ इस सुविधा को भारत के सबसे पर्यावरण-अनुकूल हवाई अड्डों में से एक बनाती हैं।

Key Points:-

(i) इसी कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने 50 किलोमीटर लंबे सेठियाथोप-चोलापुरम खंड (NH-36) को 4-लेन बनाने के लिए ₹2,350 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं और 5.16 किलोमीटर लंबे NH-138 तूतीकोरिन पोर्ट रोड को 6-लेन बनाने के लिए ₹200 करोड़ से अधिक की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं का लोकार्पण किया।

इन राजमार्ग उन्नयनों से यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आने और रसद दक्षता में वृद्धि होने की उम्मीद है।

(ii) प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ महत्वपूर्ण रेलवे और बंदरगाह परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिनमें 90 किलोमीटर लंबे मदुरै-बोडिनायक्कनूर रेलवे खंड का विद्युतीकरण, नागरकोइल-कन्याकुमारी खंड का दोहरीकरण, और वी. ओ. चिदंबरनार बंदरगाह पर नॉर्थ कार्गो बर्थ-III (क्षमता: 6.96 MMTPA, लागत: ₹285 करोड़) का शुभारंभ शामिल है।

(iii) कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र से निकासी के लिए ₹550 करोड़ की लागत वाली अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली (ISTS) भी समर्पित की गई। सामूहिक रूप से, ये पहल क्षेत्रीय व्यापार, पर्यटन और राष्ट्रीय संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक प्रमुख प्रयास को दर्शाती हैं।

4. भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन 2028 की रणनीतिक मेजबानी के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत COP-33 सेल की स्थापना की।



भारत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत एक समर्पित सीओपी-33 सेल की स्थापना की है, ताकि 2028 में जलवायु परिवर्तन

पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टिज (COP-33) के 33वें सत्र की मेजबानी की तैयारी की जा सके। यह भारत के लिए एक प्रमुख कूटनीतिक और पर्यावरणीय मील का पत्थर है क्योंकि यह वैश्विक जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए खुद को तैयार करता है।

- COP-33 प्रकोष्ठ को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक संस्थागत तंत्र के रूप में स्थापित किया गया है ताकि शिखर सम्मेलन की अंतर-मंत्रालयी, अंतर्राष्ट्रीय और रसद संबंधी तैयारियों का समन्वय किया जा सके। यह केंद्रीय योजना और कार्यान्वयन निकाय के रूप में कार्य करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि भारत का जलवायु नेतृत्व, पेरिस समझौते के तहत प्रतिबद्धताएँ और सतत विकास लक्ष्य वैश्विक मंच पर प्रभावी ढंग से उजागर हों।

- COP-33 के लिए मेजबान के रूप में भारत का चयन, उसके सक्रिय जलवायु कार्यों की मान्यता है, जैसे कि ग्लासगो में COP-26 में घोषित पंचामृत प्रतिज्ञाएँ, जहां भारत ने 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई थी। 2028 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत को जलवायु समानता, जलवायु वित्त और विकसित देशों से विकासशील देशों में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए एक मंच प्रदान करेगी।

- यह प्रकोष्ठ भारत की विविध जलवायु पहलों में समावेशी भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए राज्यों, नागरिक समाज, शिक्षा जगत, उद्योगों और युवा संगठनों के साथ भी जुड़ेगा। उम्मीद है कि COP-33 के दौरान राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) और पर्यावरण के लिए जीवनशैली (LIFE) आंदोलन जैसे भारत के घरेलू प्रयासों को प्रदर्शित किया जाएगा।

Key Points:-

(i) 2028 का जलवायु शिखर सम्मेलन महत्वपूर्ण वैश्विक जलवायु समय-सीमाओं के साथ भी मेल खाएगा, जिसमें वैश्विक समीक्षा और अद्यतन राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDCs) की प्रगति समीक्षा भी शामिल है। भारत इस अवसर का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा, वानिकी, सतत परिवहन और अनुकूलन के क्षेत्र में अपनी उन्नत जलवायु कार्रवाइयों को प्रस्तुत करने के लिए करना चाहता है।

(ii) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विदेश मंत्रालय (MEA) और नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारी योजना ढांचे का हिस्सा हैं, और सीओपी-33 के लिए मेजबान शहर को 2026 तक अंतिम रूप दिए जाने की उम्मीद है। 1992 में UNFCCC की स्थापना के बाद से यह पहली बार होगा जब भारत सीओपी शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, जिससे यह भारत की जलवायु कूटनीति में एक ऐतिहासिक घटना बन जाएगी।

5. भारत 1999 के युद्ध के बहादुर सैनिकों को सम्मानित करते हुए 26 जुलाई 2025 को कारगिल विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाई।



26 जुलाई 2025 को, भारत ने 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी घुसपैठियों से भारतीय क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने वाले भारतीय सैनिकों के अद्वितीय शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए कारगिल

विजय दिवस की 26वीं वर्षगांठ मनाई। इस दिन को राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाया गया और भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता को याद किया गया।

- कारगिल युद्ध मई 1999 में शुरू हुआ जब लगभग 1,500 पाकिस्तानी सैनिकों और आतंकवादियों ने नियंत्रण रेखा (LoC) पार करके जम्मू और कश्मीर (अब लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश) के कारगिल सेक्टर में भारतीय सीमा में घुसपैठ की। उनका मुख्य उद्देश्य रणनीतिक श्रीनगर-लेह मार्ग को बाधित करना और भारत पर कूटनीतिक और सैन्य दबाव बनाना था।

- जवाब में, भारतीय सेना ने कब्जे वाली चोटियों को वापस पाने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया। 60 दिनों से ज़्यादा समय तक भीषण युद्ध चला, जिसके परिणामस्वरूप 26 जुलाई 1999 तक घुसपैठियों को पूरी तरह से खदेड़ दिया गया। यह जीत भारी कीमत पर मिली, जो भारत की अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

- इस भीषण युद्ध के दौरान, 545 भारतीय सैनिकों ने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उनकी वीरता को 4 परमवीर चक्र (PVCs), 9 महावीर चक्र (MVCs) और 55 वीर चक्र (VCs) सहित वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जो युद्ध में निस्वार्थ सेवा और बलिदान की सर्वोच्च परंपराओं का प्रतीक हैं।

Key Points:-

(i) 2025 में आधिकारिक कारगिल विजय दिवस समारोह लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पर आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहीद वीरों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत के युवाओं और सशस्त्र बलों के लिए उनकी निरंतर प्रेरणा को स्वीकार किया।

(ii) उसी दिन, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय

(MoYAS) ने मेरा युवा भारत (MY Bharat) के माध्यम से द्रास में कारगिल विजय दिवस पदयात्रा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में देश भर के युवा प्रतिभागी राष्ट्रवाद की भावना का सम्मान करने और कारगिल युद्ध के दौरान सैनिकों द्वारा दिखाए गए साहस को याद करने के लिए एकत्रित हुए।

(iii) कारगिल विजय दिवस भारत की सैन्य शक्ति और एकता का राष्ट्रीय प्रतीक है। यह इस संदेश को पुष्ट करता है कि भारत की ज़मीन के एक-एक इंच की हर कीमत पर रक्षा की जाएगी। इस वार्षिक समारोह का उद्देश्य आधुनिक भारतीय सैन्य इतिहास को आकार देने वाली वीरता की कहानियों को जीवित रखना भी है।

6. NCERT कक्षा 3-12 में ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला और ऑपरेशन सिंदूर पर पाठ्यक्रम मॉड्यूल शुरू करेगा।



एक महत्वपूर्ण शैक्षिक विकास में, NCERT कक्षा 3 से 12 तक के लिए नए पाठ्यक्रम मॉड्यूल शुरू करने की तैयारी कर रहा है ताकि अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में भारत की हालिया उपलब्धियों, खासकर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के ऐतिहासिक ISS मिशन और ऑपरेशन सिंदूर की सैन्य सफलता, पर प्रकाश डाला जा सके।

● यह पहल राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के उस दृष्टिकोण के अनुरूप है जिसके तहत स्कूली शिक्षा में राष्ट्रीय गौरव और समकालीन उपलब्धियों को शामिल किया जाना है।

● NCERT दो अलग-अलग मॉड्यूल विकसित कर रहा है: एक कक्षा 3-8 के लिए और दूसरा कक्षा 9-12 के लिए, प्रत्येक 8-10 पृष्ठों का। ये मॉड्यूल उम्र के अनुसार विषय-वस्तु की संरचना करेंगे, छोटे छात्रों के लिए सरलीकृत कथाएँ और बड़े छात्रों के लिए विस्तृत रणनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे।

● ऑपरेशन सिंदूर—22 अप्रैल के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को शुरू किया गया सटीक सैन्य हमला—भारत की आतंकवाद-रोधी क्षमताओं को दर्शाने वाले एक केस स्टडी के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। छात्र सीखेंगे कि कैसे समन्वित रक्षा, कूटनीति और अंतर-मंत्रालयी पहलों ने रणनीतिक सफलता सुनिश्चित की।

Key Points:-

(i) ये मॉड्यूल ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (एक्सिओम मिशन 4) जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे, के योगदान का जश्न मनाएंगे। कक्षा 5 के EVS में एक उल्लेखनीय उद्धरण ("पृथ्वी पूरी तरह से एक दिखती है; बाहर से कोई सीमा दिखाई नहीं देती") एकता और वैश्विक नागरिकता पर जोर देता है।

(ii) मॉड्यूल के अतिरिक्त खंड भारत की मिशन लाइफ पहल, विभाजन की त्रासदी और चंद्रयान तथा आदित्य एल1 सहित प्रमुख अंतरिक्ष अभियानों पर चर्चा करेंगे। इन समावेशों का उद्देश्य रक्षा, पर्यावरण संरक्षण और वैज्ञानिक उत्कृष्टता को शिक्षण में शामिल करना है।

(iii) पूर्व सैनिकों और शिक्षाविदों ने इस कदम का स्वागत किया है। सेवानिवृत्त अधिकारी इसे देशभक्ति का एक ऐसा मील का पत्थर बताते हैं जो छात्रों में राष्ट्रीय गौरव और करियर की आकांक्षाओं को प्रेरित

करेगा। यह पहल शिक्षा के माध्यम से सेवा के मूल्यों और रणनीतिक जागरूकता को बढ़ावा देने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है।

INTERNATIONAL

1. यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को 2025 का विश्व का सबसे सुंदर हवाई अड्डा घोषित किया गया।



जुलाई 2025 में, प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स आर्किटेक्चर अवार्ड्स ने चीन में यंताई पेंगलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को 2025 का दुनिया का सबसे सुंदर हवाई अड्डा माना। टर्मिनल ने पारिस्थितिक स्थिरता, क्षेत्रीय पहचान और कलात्मक वास्तुकला को एक आकर्षक, कार्यात्मक डिजाइन में एकीकृत करने के लिए प्रशंसा प्राप्त की।

● यंताई, शेडोंग प्रांत (चीन) में एक नया टर्मिनल, टर्मिनल 2 (167,000 वर्ग मीटर में फैला), Aedas, CSWAD और शंघाई न्यू एरा एयरपोर्ट डिज़ाइन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किया गया है। आधिकारिक तौर पर 2024 के मध्य में खुलने वाले इस टर्मिनल का लेआउट ई-आकार का है, जो पास के कुन्यू पर्वत और तटीय रूपांकनों से प्रेरित है, जो पर्यावरणीय प्रभाव को कम करते हुए यात्री प्रवाह को अनुकूलित करता है। आंतरिक वक्र और सामग्री लकड़ी के जहाज के पतवारों की याद दिलाते हैं, जो

समुद्री रेशम मार्ग की विरासत को श्रद्धांजलि देते हैं। एक बहु-स्तरीय प्रांगण के ऊपर एक चमकदार डायग्रिड गुंबद के माध्यम से प्राकृतिक प्रकाश पूरे स्थान में व्याप्त है।

- फ्रांस के मार्सिले प्रोवेंस हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 को पुराने बंदरगाह से प्रेरित 70% पुनर्नवीनीकृत स्टील और लकड़ी के आंतरिक सज्जा के लिए सम्मानित किया गया। रीयूनियन के रोलांड गैरोस हवाई अड्डे की प्राकृतिक वायुसंचार और स्थानीय वनस्पतियों सहित उष्णकटिबंधीय जैव-जलवायु डिज़ाइन के लिए प्रशंसा की गई।

- जापान में कंसाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 ने स्मार्ट कतार प्रणालियों और प्राकृतिक सामग्रियों से क्षमता में 25% की वृद्धि की। अमेरिका के पोर्टलैंड हवाई अड्डे में स्थानीय लकड़ी का उपयोग करके बड़े पैमाने पर लकड़ी की छत बनाई गई, जबकि सैन फ्रांसिस्को के हार्वे मिल्क टर्मिनल ने कार्बन उत्सर्जन में 79% की कमी की और दुनिया का एकमात्र मान्यता प्राप्त हवाई अड्डा कला संग्रहालय भी यहाँ स्थित है।

Key Points:-

(i) इन पुरस्कारों ने न केवल सौंदर्यबोध को, बल्कि हवाई अड्डों की परिचालन, पारिस्थितिक और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में उनकी भूमिका को भी मान्यता दी। प्रिक्स वर्सेल्स के महासचिव जेरोम गौडैन के अनुसार, ये नए हवाई अड्डे उन्नत प्रवाह समाधानों और क्षेत्रीय स्थापत्य सौंदर्य का मिश्रण हैं, जो पारगमन स्थलों को "कलाकृतियों" में बदल देते हैं। मूल्य निर्धारण मानदंडों में स्थिरता, यात्री अनुभव और स्थानीय विरासत का प्रतिबिंब शामिल थे।

(ii) सिंगापुर के चांगी हवाई अड्डे जैसे लंबे समय से पसंदीदा टर्मिनल पर यंताई टर्मिनल 2 की जीत, जो 2025 की सूची में शामिल नहीं था, सार्वजनिक बुनियादी ढांचे में चीन के बढ़ते वास्तुशिल्प प्रभाव को रेखांकित करती है। छह विजेता टर्मिनलों में से तीन

को दिसंबर 2025 में विशेष विश्व खिताब (प्रिक्स वर्सेल्स, इंटीरियर या एक्सटीरियर) प्राप्त होंगे।

(iii) 2025 की सूची हवाई अड्डे की वास्तुकला में निरंतर बदलाव का प्रतीक है — हवाई अड्डे अब केवल पारगमन बिंदु नहीं रह गए हैं, बल्कि पहचान, स्थिरता और डिज़ाइन उत्कृष्टता की अभिव्यक्ति हैं। यंताई पेंगलाई का टर्मिनल 2 इस बात का एक नया मानक स्थापित करता है कि कैसे एक हवाई अड्डा क्षेत्रीय गौरव, यात्री प्रवाह और पर्यावरणीय ज़िम्मेदारी को आकार दे सकता है।

2. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड किंगडम की दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा के दौरान 'भारत-UK विजन 2035' का शुभारंभ किया।



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दो देशों (UK और मालदीव) के राजनयिक दौरे के पहले चरण के तहत 23 जुलाई से 24 जुलाई, 2025 तक यूनाइटेड किंगडम की दो दिवसीय यात्रा संपन्न की।

- यह यात्रा ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के औपचारिक निमंत्रण पर की गई, जिसमें रणनीतिक द्विपक्षीय वार्ता, कूटनीतिक जुड़ाव और दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया।

- यह यात्रा 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से पीएम मोदी की यूनाइटेड किंगडम की चौथी

आधिकारिक यात्रा थी। वह लंदन हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां उनका स्वागत इंडो-पैसिफिक के लिए यूके के विदेश कार्यालय मंत्री कैथरीन वेस्ट, साथ ही UK में भारतीय उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी और भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त लिंडी कैमरन ने किया।

- इस यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने बकिंघमशायर के चेकर्स स्थित अपने आधिकारिक निवास पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक में रणनीतिक सहयोग को मज़बूत करने, व्यापार और निवेश को बढ़ाने, और जलवायु कार्रवाई तथा वैश्विक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में संयुक्त प्रयासों को मज़बूत करने पर चर्चा हुई।

Key Points:-

(i) इस यात्रा का एक प्रमुख आकर्षण 'भारत-यूके विज़न 2035' का आधिकारिक शुभारंभ था, जो 2021 में हस्ताक्षरित पहले के 'भारत-यूके 2030 रोडमैप' का स्थान लेता है। नए ढांचे का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में आर्थिक विकास, डिजिटल नवाचार, स्वास्थ्य सेवा, सुरक्षा, शिक्षा, रक्षा और जलवायु प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों का मार्गदर्शन करना है।

(ii) नव-प्रवर्तित विज़न 2035, भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी (CSP) को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें गहन संस्थागत सहयोग और लोगों के बीच बेहतर संबंध शामिल हैं। यह समावेशी, तकनीक-संचालित विकास के माध्यम से पारस्परिक विकास पर ज़ोर देता है, और दीर्घकालिक आर्थिक लचीलेपन और सतत नवाचार पर केंद्रित है।

(iii) सांस्कृतिक मोर्चे पर, प्रधानमंत्री मोदी ने महामहिम राजा चार्ल्स तृतीय से उनके ग्रीष्मकालीन निवास, सैंड्रिंघम एस्टेट में मुलाकात की। इस बातचीत के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की 'एक पेड़ माँ के नाम' पहल के तहत राजा को 'सोनोमा' वृक्ष (डेविडिया इनवोलुक्रेटा) का एक पौधा भेंट किया, जो

भारत की हरित कूटनीति और प्रकृति-आधारित वैश्विक साझेदारी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

BANKING & FINANCE

1. Xflow को क्रॉस-बॉर्डर भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए RBI की सैद्धांतिक मंजूरी मिली।



जुलाई 2025 में, बेंगलुरु स्थित फिनटेक कंपनी Xflow को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) से क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर (PA-CB) के रूप में संचालन के लिए इन-प्रिंसिपल ऑथराइज़ेशन (IPA) प्राप्त हुआ है। यह मंजूरी Xflow के लिए अंतरराष्ट्रीय डिजिटल भुगतान और विदेशी मुद्रा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

- RBI की इस सैद्धांतिक स्वीकृति से Xflow अब भारतीय व्यवसायों के लिए निर्यात और आयात दोनों प्रकार के अंतरराष्ट्रीय भुगतान प्रवाह को संभाल सकता है। PA-CB के रूप में, Xflow अब क्रॉस-बॉर्डर पेमेंट्स के लिए पूरी तरह से डिजिटल, सुरक्षित और अनुपालन-सम्मत समाधान प्रदान कर सकता है।

- इस नई मंजूरी के साथ, Xflow ने वर्ष 2025 के अंत तक अपने ग्राहक आधार को 10,000 से बढ़ाकर 30,000 व्यवसायों तक पहुंचाने की योजना बनाई है।

- यह रणनीतिक विस्तार विशेष रूप से MSMEs (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों) के लिए मददगार होगा, जो अक्सर अंतरराष्ट्रीय लेनदेन में जटिलताओं का सामना करते हैं।

Key Points:-

(i) Xflow ने एक नया टूल FX AI Analyst भी लॉन्च किया है, जिसे भारत का पहला AI-संचालित विदेशी मुद्रा विश्लेषण टूल माना जा रहा है। यह टूल व्यापारिक संस्थाओं को करेंसी कन्वर्जन को अनुकूलित करने और फॉरेक्स जोखिम को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करेगा।

(ii) इस स्वीकृति के साथ, Xflow अब भारत में RBI द्वारा मान्यता प्राप्त चुनिंदा PA-CBs की सूची में शामिल हो गया है। अब तक केवल 6 कंपनियों को यह अनुमति मिली है: Adyen India, Amazon Pay India, Cashfree Payments, Indialdeas.com (BillDesk), Pay10 Services, और Worldline ePayments India, जो इस उपलब्धि की विशिष्टता को दर्शाता है।

(iii) PA-CB फ्रेमवर्क RBI द्वारा विदेशी भुगतान को FEMA (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम) के तहत सुरक्षित, प्रभावी और कानूनी रूप से नियंत्रित करने के उद्देश्य से लाया गया था। Xflow की यह मंजूरी भारत में डिजिटलीकरण और फिनटेक नवाचार के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता के साथ पूरी तरह मेल खाती है।



रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्यरत और अनुसूची 'A' उद्यम के रूप में वर्गीकृत, भारत के रक्षा एवं भारी इंजीनियरिंग क्षेत्र के सार्वजनिक उपक्रम BEML लिमिटेड ने हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) के साथ एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए हैं। BEML के दिल्ली कार्यालय में औपचारिक रूप से इस समझौते का आदान-प्रदान किया गया, जो भारत के समुद्री औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

● यह समझौता ज्ञापन स्वदेशी डिज़ाइन, नवाचार, सटीक निर्माण और व्यापक जीवनचक्र समर्थन सहित उन्नत समुद्री प्रणालियों के सह-विकास पर केंद्रित एक रणनीतिक सहयोग को गति प्रदान करता है। इस साझेदारी का लक्ष्य भारत के शिपयार्ड बुनियादी ढांचे और रसद को वैश्विक मानकों के अनुरूप उन्नत करना और रक्षा एवं वाणिज्यिक समुद्री संचालन, दोनों को समर्थन प्रदान करना है।

● BEML विशिष्ट प्रणालियों के डिज़ाइन और इंजीनियरिंग का नेतृत्व करेगा, और मोबिलिटी प्लेटफॉर्म, रेल और मेट्रो प्रणालियों, मिसाइल घटकों और खनन उपकरणों में दशकों से विकसित प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग और संरचनात्मक अनुकूलन में अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाएगा। भारत की प्रमुख जहाज निर्माण सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी

ECONOMY & BUSINESS

1. BEML और HSL ने अगली पीढ़ी की समुद्री इंजीनियरिंग क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए रणनीतिक साझेदारी की।

HSL, अपने जहाज निर्माण अनुभव को BEML की मज़बूत विनिर्माण क्षमताओं के साथ एकीकृत करके स्थानीयकरण प्रयासों को गति प्रदान करेगी।

Key Points:-

(i) यह सहयोग समुद्री अवसंरचना के लिए आवश्यक प्रमुख प्रणालियों पर केंद्रित होगा: निम्न-तल परिवहन प्लेटफॉर्म, ड्रेजिंग मशीनरी, उच्च क्षमता वाली क्रेन और भारी भार वाले ट्रांसपोर्टर। ये प्रमुख प्रौद्योगिकियाँ भारत की आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत कुशल शिपयार्ड लॉजिस्टिक्स और आधुनिक समुद्री अवसंरचना की रीढ़ हैं।

(ii) BEML के CMD शांतनु रॉय के अनुसार, यह साझेदारी समुद्री क्षेत्र में कंपनी के विस्तार में एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करती है, जो समुद्री नवाचार में भारत की वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करने के लिए इंजीनियरिंग उत्कृष्टता और स्वदेशीकरण को जोड़ती है।

(iii) HSL के CMD कमोडोर हेमंत खत्री (सेवानिवृत्त) ने इस गठबंधन को "समुद्री बुनियादी ढाँचे में आत्मनिर्भरता और नवाचार की दिशा में एक रणनीतिक छलांग" बताया। BEML और HSL मिलकर समुद्री इंजीनियरिंग में भारत को अग्रणी बनाने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, जिससे भविष्य में संभावित संयुक्त उद्यमों, निर्यातों और बेहतर समुद्री तैयारी का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

APPOINTMENTS & RESIGNATIONS

1. उत्पल कुमार सिंह को संसद टीवी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया।



जुलाई 2025 में, वरिष्ठ नौकरशाह उत्पल कुमार सिंह, जो वर्तमान में लोकसभा के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं, को राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष द्वारा संसद TV का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त किया गया है। वे तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक संसद टीवी का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।

● संसद TV की गवर्निंग काउंसिल ने उत्पल कुमार सिंह को CEO की अतिरिक्त जिम्मेदारियाँ सौंपी हैं, जो रवि कपूर से अधिकार हस्तांतरित करते हैं - जिन्हें अगस्त 2022 के अंत में अपने कर्तव्यों से मुक्त कर दिया गया था। यह नियुक्ति संसद सचिवालय द्वारा प्रशासनिक निरीक्षण को बहाल करती है।

● उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी सिंह ने 30 नवंबर 2020 को लोकसभा सचिवालय के महासचिव का पदभार संभाला। उनका गहन संस्थागत अनुभव और संसदीय प्रक्रियाओं के साथ समन्वय उन्हें संसद TV का प्रभावी ढंग से नेतृत्व करने की स्थिति में रखता है।

Key Points:-

(i) लोकसभा TV और राज्यसभा TV के विलय के माध्यम से सितंबर 2021 में शुरू किया गया संसद TV, संसदीय कार्यवाही और जनहित से जुड़ी सामग्री हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित करता है। CEO के रूप में, सिंह सामग्री रणनीति, कार्यक्रम की गुणवत्ता और

लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संरक्षण की देखरेख करेंगे।

(ii) लोकसभा महासचिव को CEO नियुक्त करके, संसद निर्बाध नीति समन्वय और विषय-वस्तु की प्राथमिकता सुनिश्चित करती है। यह कदम विधायी पारदर्शिता और शासन संचार को प्रतिबिंबित करने के लिए संसद TV के जनादेश को मजबूत करता है।

(iii) उत्तराखंड में बाढ़ के बाद पुनर्वास के दौरान अपने प्रशासनिक नेतृत्व और एक विश्वसनीय कैरियर नौकरशाह के रूप में जाने जाने वाले उत्पल कुमार सिंह को एक अनुशासित, कम-प्रोफ़ाइल वाले अधिकारी के रूप में देखा जाता है जो संसद TV को संसदीय लोकतंत्र की एक विश्वसनीय आवाज़ के रूप में आकार देने में सक्षम हैं।

2. अनुराधा ठाकुर को 24 जुलाई, 2025 से RBI के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया।



भारत सरकार ने हाल ही में आर्थिक मामलों के विभाग (DEA) की सचिव अनुराधा ठाकुर को भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। उनकी नियुक्ति 24 जुलाई 2025 से प्रभावी होगी, जो भारत के केंद्रीय बैंक के सर्वोच्च निर्णय-निर्माण स्तर पर राजकोषीय और मौद्रिक नीति

तालमेल को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

● हिमाचल प्रदेश कैडर की 1994 बैच की भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारी अनुराधा ठाकुर, अजय सेठ (IAS 1987 बैच) का स्थान लेंगी, जो 30 जून 2025 को DEA सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं।

● RBI बोर्ड में उनका नामांकन आर्थिक मामलों के सचिव को सरकार द्वारा नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने की परंपरा के अनुरूप है, जो राजकोषीय और मौद्रिक क्षेत्रों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।

● अनुराधा ठाकुर ने 1 जुलाई 2025 को आर्थिक मामलों के सचिव के रूप में संस्थागत नेतृत्व ग्रहण किया, और भारत में इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला बनीं। RBI केंद्रीय बोर्ड में उनका शामिल होना वित्त मंत्रालय और RBI के बीच नीतिगत संवाद में निरंतरता सुनिश्चित करता है—खासकर तब जब देश महामारी के बाद की आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा है।

Key Points:-

(i) अनुराधा ठाकुर के पेशेवर पोर्टफोलियो में गंभीर धोखाधड़ी जाँच कार्यालय (SFIO), कॉर्पोरेट मामलों के विभाग और निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) जैसे विभागों से संबद्धता शामिल है। उन्होंने एयर इंडिया के विनिवेश और भारत बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के शुभारंभ जैसी पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे सार्वजनिक नीति कार्यान्वयन और वित्तीय सुधारों में उनकी विश्वसनीयता प्रदर्शित हुई।

(ii) RBI केंद्रीय बोर्ड, जहाँ वह अब वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू के साथ कार्यरत हैं, मौद्रिक नीति निर्माण, बैंकिंग विनियमन और वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की देखरेख के लिए जिम्मेदार है। उनकी नियुक्ति 4-6 अगस्त 2025 को होने वाली मौद्रिक

नीति समिति (MPC) की बैठक से ठीक पहले हुई है, जहाँ नीतिगत रुखों में आँकड़ों पर आधारित दृष्टिकोण और व्यापक आर्थिक उद्देश्यों, दोनों को प्रतिबिंबित करने की उम्मीद है।

(iii) अनुराधा ठाकुर का नामांकन आर्थिक नीति निर्माण में समावेशी नेतृत्व की दिशा में भारत के विकसित होते दृष्टिकोण का प्रतीक है, जो राजकोषीय शासन की शक्तियों को केंद्रीय बैंकिंग में लाता है। रणनीतिक आर्थिक पहलों और नियामक निगरानी में अपने अनुभव के साथ, वे वित्तीय समावेशन से लेकर पूंजी बाजार विकास और मुद्रास्फीति प्रबंधन तक के मुद्दों पर RBI के विचार-विमर्श को प्रभावित करने के लिए तैयार हैं।

SPORTS

1. ऑस्कर पियास्त्री ने वर्षा प्रभावित 2025 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स में जीत हासिल कर चैंपियनशिप में अपनी बढ़त को बढ़ाया।



27 जुलाई 2025 को, फॉर्मूला1 2025 विश्व चैंपियनशिप के 13वें दौर के लिए बेल्जियम के प्रसिद्ध सर्किट डे स्पा-फ्रैंकोरचैम्प्स में लौट आया। मैकलारेन-मर्सिडीज के लिए ड्राइविंग कर रहे ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज ऑस्कर पियास्त्री ने भारी बारिश के बीच अपने साथी लैंडो नॉरिस को पीछे छोड़ते हुए शानदार जीत

हासिल की, जिससे उनकी खिताब जीतने की उम्मीद और बढ़ गई।

● रेस वीकेंड मूसलाधार बारिश के बीच शुरू हुआ, जिससे शुरुआत 80 मिनट से ज़्यादा देरी से हुई और सेफ्टी कार से कई लैप पीछे रहने पड़े। आखिरकार जब रेसिंग शुरू हुई, तो पियास्त्री ने एड रुज से होते हुए केमेल स्ट्रेट तक एक निर्णायक शुरुआत की, नॉरिस को पीछे छोड़ दिया और फिर इंटरमीडिएट टायर से स्लिक टायर पर स्विच करने के बावजूद बाकी 44 लैप पर नियंत्रण बनाए रखा।

● यह जीत 2025 सीज़न में पियास्त्री की 13 रेसों में छठी जीत थी और मैकलारेन के लिए साल की छठी वन-टू फिनिश थी, नॉरिस दूसरे स्थान पर रहे। फेरारी के चार्ल्स लेक्लेर्क ने अंतिम पोडियम स्थान हासिल किया, जबकि रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन अपनी टीम को चौथे स्थान पर ले गए।

● पियास्त्री के प्रभावशाली प्रदर्शन ने चैंपियनशिप की स्थिति को भी बदल दिया: अब वह 266 अंकों के साथ ड्राइवरों की तालिका में शीर्ष पर हैं, जबकि उनके साथी नॉरिस 250 अंकों के साथ उनसे आगे हैं। मैकलारेन के कंस्ट्रक्टर्स के अंकों की संख्या बढ़कर 516 हो गई, जो दूसरे स्थान पर रहने वाली फेरारी (248) से दोगुने से भी अधिक है, जिससे उनकी बढ़त और मजबूत हो गई है।

Key Points:-

(i) इससे पहले सप्ताहांत में, पियास्त्री ने अभ्यास और स्प्रिंट क्वालीफाइंग में एकमात्र फ्री प्रैक्टिस में 1:42.022 का सबसे तेज़ लैप समय निर्धारित करके प्रभावित किया था, और उसके बाद स्पा-फ्रैंकोरचैम्प्स में स्प्रिंट पोल पोज़िशन के लिए 1:40.510 का रिकॉर्ड तोड़ समय बनाया था। हालाँकि वह स्प्रिंट रेस में रेड बुल के मैक्स वेरस्टैपेन से हार गए, लेकिन पियास्त्री की स्पा सफलता ने विभिन्न परिस्थितियों में उनकी क्रेश-प्रूफ स्थिरता और धैर्य को उजागर किया।

(ii) स्पा के अप्रत्याशित मौसम और नए सिरे से तैयार

किए गए ट्रैक कॉर्नर को इस सप्ताहांत वाइल्डकार्ड कारक माना जा रहा था, फिर भी पियास्त्री अडिग रहे। उनकी जीत 2012 में जेनसन बटन के बाद मैकलारेन की पहली बेल्जियम ग्रां प्री जीत भी थी, जो प्रदर्शन के एक नए युग में टीम के पुनरुत्थान में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई।

2. दिव्या देशमुख ने FIDE महिला शतरंज विश्व कप 2025 जीतकर इतिहास रच दिया।



उन्नीस वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय मास्टर (IM) दिव्या देशमुख ने 28 जुलाई 2025 को भारतीय शतरंज के इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया, वह फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचेक्स (FIDE) महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई।

● जॉर्जिया के बटुमी में अनुभवी हमवतन ग्रैंडमास्टर कोनेरू हम्पी के खिलाफ मिली जीत ने दिव्या को प्रतिष्ठित ग्रैंडमास्टर का खिताब दिलाया और भारतीय शतरंज के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बन गई।

● दिव्या की सफलता की राह में शीर्ष वरीय प्रतिद्वंद्वियों पर निर्णायक जीत शामिल थी। उन्होंने क्वार्टर फ़ाइनल में ग्रैंडमास्टर हरिका द्रोणावल्ली को रैपिड प्लेऑफ़ में 2-0 से हराकर चौका दिया और एक रोमांचक सेमीफ़ाइनल में पूर्व महिला विश्व चैंपियन चीन की टैन झोंगयी को हराकर 1.5-0.5 के

स्कोर के साथ फ़ाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। इन जीतों ने उन्हें प्रतिष्ठित ग्रैंडमास्टर नॉर्म और महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 के लिए योग्यता भी दिलाई।

Key Points:-

(i) कोनेरू हम्पी के खिलाफ ऐतिहासिक फाइनल मैच में, दोनों क्लासिकल गेम ड्रॉ रहे। मैच रैपिड टाई-ब्रेकर तक पहुँचा, जहाँ दिव्या ने अद्भुत संयम और रणनीतिक सटीकता का परिचय देते हुए दूसरा टाई-ब्रेक 1.5-0.5 से जीत लिया और अंततः विजय के आँसुओं के बीच विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम कर ली।

(ii) इस जीत ने दिव्या के करियर को भी बदल दिया: वह भारत की 88वीं ग्रैंडमास्टर और ग्रैंडमास्टर का खिताब जीतने वाली केवल चौथी भारतीय महिला बनीं, कोनेरू हम्पी, हरिका द्रोणावल्ली और आर. वैशाली की श्रेणी में शामिल हुईं। उनके प्रदर्शन की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित राष्ट्रीय नेताओं ने प्रशंसा की और उनकी जीत को भारतीय महिला शतरंज में एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया।

(iii) दिव्या देशमुख की जीत भारतीय शतरंज प्रतिभा की एक नई पीढ़ी के उदय का प्रतीक है, और उनकी जीत देश भर की युवा महिलाओं के लिए एक सशक्त प्रेरणा का स्रोत भी है। खेल मनोविज्ञान और प्रदर्शन विज्ञान में उनकी संतुलित शैक्षणिक गतिविधियाँ, उनकी खेल सफलता के साथ, आधुनिक शतरंज उत्कृष्टता में शिक्षा और मानसिकता की उभरती भूमिका को दर्शाती हैं।

AWARDS

1. संसद रत्न पुरस्कार 2025 में अनुकरणीय संसदीय योगदान के लिए 17 सांसदों को सम्मानित किया गया।



26 जुलाई 2025 को, संसदीय कार्यवाही, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए 17 संसद सदस्यों (MPs) को संसद रत्न पुरस्कार 2025 प्रदान किए गए।

- ये पुरस्कार, जो अब अपने 15वें संस्करण में हैं, 2010 में अपनी स्थापना के बाद से विधायी कार्य में उत्कृष्टता का जश्न मनाते हैं, जो डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के आदर्शों से प्रेरित हैं।

- संसद रत्न पुरस्कार 2025 समारोह नई दिल्ली में आयोजित किया गया और इसका आयोजन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन ने संसद रत्न पुरस्कार समिति के सहयोग से किया। इस पुरस्कार के तहत लोकसभा और राज्यसभा के 17 प्रतिष्ठित सांसदों को बहस, निजी विधेयकों, प्रश्नों और समग्र उपस्थिति में उनके असाधारण प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया। उल्लेखनीय पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में सुप्रिया सुले, रवि किशन, निशिकांत दुबे और अरविंद सावंत शामिल थे।

- विशेष जूरी पुरस्कार श्रेणी की शुरुआत उन सांसदों को सम्मानित करने के लिए की गई थी जिन्होंने 16वीं लोकसभा के बाद से लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष, विशेष जूरी पुरस्कार भर्तृहरि महताब, एन.के. प्रेमचंद्रन, सुप्रिया सुले और श्रीरंग अप्पा बार्ने को प्रदान किए गए। इन सांसदों को गुणवत्तापूर्ण विधायी योगदान और जन

जवाबदेही के प्रति उनकी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता के लिए सम्मानित किया गया।

Key Points:-

(i) व्यक्तिगत सम्मानों के अलावा, वित्त और कृषि संबंधी स्थायी समितियों को भी सम्मानित किया गया। इन समितियों को राष्ट्रीय नीति निर्माण, लोकतांत्रिक मूल्यों को बढ़ावा देने, विधायी जाँच सुनिश्चित करने और कार्यपालिका को जवाबदेह बनाने में उनकी सशक्त भूमिका के लिए सम्मानित किया गया। इनका कार्य भारत के संसदीय कामकाज में समितियों के बढ़ते महत्व को दर्शाता है।

(ii) संसद रत्न पुरस्कारों को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास (IIT-M) और ई-पत्रिका "प्रीसेंस" सहित प्रमुख संस्थानों द्वारा समर्थित किया जाता है। ये पुरस्कार कार्य-आधारित मान्यता के माध्यम से लोकतंत्र को मज़बूत करने के लक्ष्य के अनुरूप हैं, जिससे सांसदों को गुणवत्तापूर्ण विधायी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित किया जा सके। यह पहल सांसदों के योगदान के डेटा-आधारित मूल्यांकन के महत्व की ओर भी ध्यान आकर्षित करती है।

(iii) ये पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम के सुझाव पर 2010 में शुरू किए गए थे, जिन्होंने लोकतांत्रिक संस्थाओं में पारदर्शिता और मान्यता की संस्कृति की कल्पना की थी। तब से, ये पुरस्कार विधायी उत्कृष्टता के लिए भारत के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक बन गए हैं, जो भारतीय संसद और पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (PRS - संसदीय अनुसंधान सेवाएँ) के सत्यापित आंकड़ों पर आधारित हैं।

SUMMITS & CONFERENCE / COMMITTEES & MEETINGS

1. भारत ने सतत अस्पताल योजना पर पहली बार SHAPE 2025 सम्मेलन की मेजबानी की।



एक अभूतपूर्व पहल के तहत, भारत ने आर्मी हॉस्पिटल (रिसर्च एंड रेफरल) के अस्पताल प्रशासन विभाग के माध्यम से जुलाई 2025 में नई दिल्ली में SHAPE 2025 (सतत अस्पताल वास्तुकला, योजना, बुनियादी ढाँचा और उपकरण) का आयोजन किया, जो अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन था। इस ऐतिहासिक आयोजन में नागरिक और सैन्य स्वास्थ्य सेवा विशेषज्ञों ने भारत के स्वास्थ्य सेवा बुनियादी ढाँचे के लिए भविष्य के लिए तैयार रोडमैप तैयार करने हेतु एक मंच तैयार किया।

- पहले SHAPE 2025 सम्मेलन में, सशस्त्र बलों, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं, अस्पतालों और वास्तुशिल्प डिज़ाइन क्षेत्रों के 275 से अधिक पेशेवरों ने टिकाऊ डिज़ाइन, लचीले बुनियादी ढाँचे और उन्नत उपकरण एकीकरण जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए भाग लिया। प्रतिभागियों में अस्पताल प्रशासक, डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर और आर्किटेक्ट शामिल थे।

- यह सम्मेलन राष्ट्रीय लचीलेपन और स्थिरता लक्ष्यों के साथ संरेखित भविष्य की स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना की दिशा में एक रणनीतिक धुरी का प्रतीक है।

Key Points:-

(i) सतत चिकित्सा शिक्षा (CME) कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा

महानिदेशक, सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (नई दिल्ली) के निदेशक डॉ. एम. श्रीनिवास ने किया। उनकी उपस्थिति ने अस्पताल नियोजन के भविष्य को आकार देने में सैन्य परिशुद्धता और चिकित्सा उत्कृष्टता के समन्वय को रेखांकित किया।

(ii) SHAPE 2025 ने एकीकृत, हरित अस्पताल नियोजन ढाँचों पर ज़ोर दिया। सत्रों में गृह (एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए हरित रेटिंग) और CFEEES (प्रमाणित सुविधा ऊर्जा दक्षता मानक) प्रमाणन प्राप्त करने के लिए विस्तृत मॉडलों पर चर्चा की गई, और रोगी सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए सौर एकीकरण, वर्षा जल संचयन, आपदा-रोधी लेआउट और शून्य-उत्सर्जन परिचालन प्रोटोकॉल जैसे डिज़ाइन तत्वों का प्रदर्शन किया गया।

(iii) सम्मेलन ने भारत में स्थायी अस्पताल अवसंरचना पर एक प्रस्तावित सिद्धांत की नींव भी रखी, जिसका उद्देश्य भविष्य की सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवा परियोजनाओं का मार्गदर्शन करना है। यह सिद्धांत अस्पताल के डिज़ाइन, अवसंरचना के लचीलेपन, श्रम-दक्षता संबंधी सुविधाओं और हरित भवन मानदंडों का मानकीकरण करेगा—जिससे यह स्वास्थ्य-सुरक्षित विकासात्मक प्रतिमान के तहत भारत के दीर्घकालिक दृष्टिकोण, विकसित भारत @2047 के अनुरूप होगा।

IMPORTANT DAYS

1. संयुक्त राष्ट्र 25 जुलाई 2025 को अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया।



25 जुलाई 2025 को, संयुक्त राष्ट्र ने अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया, जो उनके योगदान, शक्ति और नेतृत्व को वैश्विक मान्यता प्रदान करता है। यह दिन दुनिया भर में अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों के समावेश, सशक्तिकरण और समानता की आवश्यकता का एक सशक्त अनुस्मारक है।

- 2025 में अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के पहले आयोजन का विषय था "एक साथ उठना: अफ्रीकी मूल की महिलाएं और लड़कियां ताकत के साथ नेतृत्व करें", जिसमें ऐतिहासिक बहिष्कार और असमानता के सामने एकता, सशक्तिकरण और नेतृत्व पर जोर दिया गया था।

- संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने 13 अगस्त 2024 को संकल्प A/RES/78/323 के माध्यम से आधिकारिक तौर पर इस दिन को अपनाया, जिसमें अफ्रीकी विरासत की महिलाओं और लड़कियों की उपलब्धियों और चुनौतियों को पहचानने के लिए अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का आह्वान किया गया।

- इस प्रस्ताव को प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं जैसे कि UN Women (लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संस्था), OHCHR (मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त का कार्यालय) और UNESCO (संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक,

वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन) द्वारा जोरदार समर्थन दिया गया, जिन्होंने सामूहिक रूप से इस वैश्विक मान्यता की वकालत की।

Key Points:-

(i) यह अंतर्राष्ट्रीय दिवस विकास एजेंडा के भीतर विविधता और समावेशिता के महत्व पर प्रकाश डालता है, तथा नस्लीय भेदभाव और लैंगिक पूर्वाग्रह को समाप्त करने का आह्वान करता है, साथ ही अफ्रीकी मूल की महिलाओं को वैश्विक शांति, नवाचार और लचीलेपन में महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में रेखांकित करता है।

(ii) संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सभी सदस्य देशों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, शैक्षणिक संस्थानों और मीडिया संगठनों को स्मरणोत्सव कार्यक्रमों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अफ्रीकी मूल की महिलाओं और लड़कियों की आवाज और आकांक्षाओं को सुना जाए और वैश्विक स्तर पर उन्हें बढ़ावा दिया जाए।

2. भारत 27 जुलाई 2025 को सेवा और बलिदान की विरासत का सम्मान करते हुए CRPF का 87वां स्थापना दिवस मनाया।



27 जुलाई 2025 को, भारत ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) का 87वाँ स्थापना दिवस मनाया—जो

अटूट सेवा, अनुशासन और बलिदान की गौरवशाली विरासत का प्रतीक है। भारत के सबसे बड़े केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के रूप में, CRPF आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है।

- 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में स्थापित, CRPF का दिसंबर 1949 में संसद के एक अधिनियम के तहत पुनः नामकरण किया गया। सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे नेताओं के नेतृत्व में, यह पूरे भारत में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए ज़िम्मेदार एक केंद्रीय बल के रूप में विकसित हुआ।

- गृह मंत्रालय के अधीन कार्यरत, CRPF विविध भूमिकाएँ निभाता है: उग्रवाद-रोधी, कानून-व्यवस्था लागू करना, VIP सुरक्षा, चुनाव ड्यूटी और आपदा प्रतिक्रिया। विशेष इकाइयों में रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) और कोबरा शामिल हैं, जिन्हें क्रमशः दंगा नियंत्रण और नक्सल-विरोधी अभियानों के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

- दशकों से, CRPF प्रमुख अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है: उग्रवाद से निपटना, संसदीय-आतंकवादी हमलों को विफल करना और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सहायता प्रदान करना। इसके कर्मियों को अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र और जॉर्ज क्रॉस जैसे प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हुए हैं, और 2,255 से अधिक कर्मियों ने सेवा में अपने प्राणों की आहुति दी है।

Key Points:-

(i) 2025 में, स्थापना दिवस पूरे देश में परेड, शहीद स्मारकों पर पुष्पांजलि, सामुदायिक संपर्क, "फिट इंडिया" साइकिल रैलियाँ और वृक्षारोपण जैसे कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। नागपुर स्थित 37वीं बटालियन में, कमांडेंट दाओ इंजिरकन किंडो और वरिष्ठ अधिकारियों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और देशभक्ति की भावना को मज़बूत करते

हुए स्मरणोत्सव का नेतृत्व किया।

(ii) 246-247 बटालियनों में 3.1 लाख से अधिक सक्रिय कर्मियों के साथ, CRPF भारत की आंतरिक सुरक्षा संरचना के लिए एक आवश्यक अंग बना हुआ है। "सेवा और निष्ठा" के आदर्श वाक्य पर निर्मित एक बल के रूप में, इसकी विरासत भारत के लचीलेपन, सतर्कता और बदलते सुरक्षा परिदृश्यों के अनुकूल ढलने की क्षमता को रेखांकित करती है।

SCIENCE AND TECHNOLOGY

1. रूस ने वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से ईरान के नाहिद-2 सहित 20 उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।



अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ाने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, रूस ने 25 जुलाई, 2025 को सोयुज़-2.1b वाहक रॉकेट का उपयोग करके कुल 20 उपग्रहों का प्रक्षेपण किया, जिनमें ईरान का एक उपग्रह भी शामिल है। यह प्रक्षेपण रूस के अमूर ओब्लास्ट स्थित वोस्तोचनी कॉस्मोड्रोम से हुआ और इसमें कई वैज्ञानिक और संचार पेलोड शामिल थे।

- इस प्रक्षेपण में आयनोस्फीयर-M कार्यक्रम के तहत रूस के दो प्रमुख पृथ्वी अवलोकन उपग्रह (EOS), रूसी कंपनियों और संस्थानों द्वारा निर्मित 17 छोटे उपग्रह और ईरान द्वारा विकसित नाहिद-2 संचार उपग्रह शामिल थे। यह मिशन अंतरराष्ट्रीय

अंतरिक्ष एजेंसियों, विशेष रूप से ईरान के अंतरिक्ष संगठनों के साथ रूस की बढ़ती साझेदारी को दर्शाता है।

दिया गया था।

- ईरान का नाहिद-2 उपग्रह, जिसका फ़ारसी में अर्थ "शुक्र" है, ईरानी अंतरिक्ष एजेंसी (ISA) द्वारा ईरानी अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र (ISRC) के सहयोग से विकसित किया गया है। 110 किलोग्राम वज़नी नाहिद-2 को पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर एक कक्षा में स्थापित किया गया है और इसके दो साल तक काम करने की उम्मीद है। इसे ईरान में नागरिक संचार अवसंरचना को मज़बूत करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- नाहिद-2 तैनात करने योग्य सौर पैनलों से सुसज्जित है और दूरसंचार सिग्नल भेज और प्राप्त कर सकता है। इसका मुख्य कार्य ईरान के घरेलू संचार नेटवर्क विकास में सहायता करना है और यह देश की स्वतंत्र अंतरिक्ष क्षमताओं में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

Key Points:-

(i) रूस के आयनमंडल-M पृथ्वी अवलोकन उपग्रह संख्या 3 और संख्या 4 इस प्रक्षेपण के प्राथमिक पेलोड थे। इन उपग्रहों का उद्देश्य पृथ्वी के आयनमंडल का अध्ययन करना और वायुमंडलीय मौसम, विकिरण स्तर और प्राकृतिक एवं मानवजनित कारकों से प्रभावित अन्य भूभौतिकीय प्रक्रियाओं पर आँकड़े एकत्र करना है।

(ii) इसमें शामिल 17 छोटे उपग्रहों में से 9 रूसी कंपनी जियोस्कैन द्वारा विकसित किए गए हैं, जो पृथ्वी की इमेजिंग और निगरानी में विशेषज्ञता रखती है। इन उपग्रहों का उपयोग यातायात निगरानी और अंतरिक्ष विज्ञान में अकादमिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाएगा।

(iii) ग्रह विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोगी परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए रूस-ईरान अंतरिक्ष साझेदारी को पहले जनवरी 2025 में औपचारिक रूप

Static GK

the United Kingdom (UK)	राजधानी : लंदन	प्रधानमंत्री (PM) : कीर स्टारमर
BEML Limited	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक: शांतनु रॉय	मुख्यालय: बेंगलुरु
RBI	राज्यपाल: संजय मल्होत्रा	मुख्यालय: मुंबई
Russia	राष्ट्रपति: व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन	मुद्रा: रूसी रूबल
UN Women	कार्यकारी निदेशक : सिमा सामी बहौस	मुख्यालय : न्यूयॉर्क शहर, (USA)